लैंगिक विभाजन

लेखक - सोनालदे देसाई (समाजशास्त्र की प्रोफेसर, मैरीलैंड विश्वविद्यालय, यू.एस.)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र- II (सामाजिक मुद्दे) से संबंधित है।

द हिन्दू

12 जून, 2019

"यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है कि काम पाने में असमर्थ महिलाएँ श्रम शक्ति से बाहर निकल रही हैं।"

यदि श्रम शक्ति सर्वेक्षण के आंकड़ों पर विश्वास किया जाए, तो ग्रामीण भारत एक लैंगिक क्रांति के बीच है, जिसमें 2004-05 में काम करने वाली लगभग आधी महिलाएँ 2017-18 में बाहर हो गई थीं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के 61वें दौर में 15 वर्ष से अधिक उम्र की 48.5% ग्रामीण महिलाओं को या तो प्रमुख गतिविधि के रूप में या सहायक गतिविधि के रूप में नियोजित किया गया, लेकिन हाल ही में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) द्वारा जारी रिपोर्ट में यह संख्या 23.7% तक गिर गई। क्या यह ग्रामीण जीवन शैली के व्यापक परिवर्तन का हिस्सा है या हमारा सर्वेक्षण एक अलग ही तस्वीर दिखा रही हैं? यदि यह परिवर्तन वास्तविक है, तो यह वास्तव में चिंता का कारण है?

वृद्धिशील गिरावट

इससे पहले कि हम इन परिवर्तनों की जाँच करें। यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा काम की भागीदारी में गिरावट अचानक नहीं आई है। पीएलएफएस के नवीनतम आंकड़ों में बस एक प्रवृत्ति जारी है, जो 2011-12 तक ठीक थी। 15 से अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं के लिए कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2004-05 में 48.5% से घटकर 2011-12 में 35.2% और फिर 2017-18 में 23.7% हो गया। इसके विपरीत, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु की शहरी महिलाओं के लिए डब्ल्यूपीआर में मामूली रूप से गिरावट आई, जो 2004-05 में 22.7% से बदलकर 2011-12 में 19.5% और 2017-18 में 18.2% हो गई।

कोई भी ग्रामीण महिला डब्ल्यूपीआर में इस गिरावट को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीकों से देख सकता हैं। अगर बढ़ती आय से परिवारों में यह तय होता है कि महिलाओं का समय घर और बच्चों की देखभाल करने में बेहतर है, तो यह उनकी पसंद है। हालांकि, अगर महिलाओं को एक भीड़ भरे श्रम बाजार में काम नहीं मिल पा रहा है, तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी को दर्शाता है, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है।

अगर बढ़ती हुई आय के कारण डब्ल्यूपीआर में गिरावट आ रही है, तो हम यह उम्मीद करेंगे कि यह अमीर परिवारों में हो - जहाँ प्रति व्यक्ति मासिक खर्च अधिक होता है और महिलाएँ उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। 2004-05 और 2017-18 के बीच ग्रामीण महिला डब्ल्यूपीआर की तुलना यह नहीं बताती है कि गिरावट मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी के विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के बीच स्थित है।

2004-5 और 2017-18 के बीच, महिलाओं के डब्ल्यूपीआर 30.6% से घटकर सबसे गरीब वर्ग के लिए 16.5% और सबसे अमीर वर्ग के लिए 31.8% से 19.7% तक गिर गया। इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि डब्ल्यूपीआर में अधिकांश गिरावट शिक्षा के निम्न स्तर वाली महिलाओं के बीच हुई है। अनपढ़ महिलाओं के लिए, डब्ल्यूपीआर 55% से गिरकर 29.1% हो गया, जबकि माध्यमिक शिक्षा वाली महिलाओं के लिए 30.5% से गिरकर 15.6% हो गया।

कम से कम शिक्षित और सबसे गरीब लोगों के बीच कुछ हद तक उच्च एकाग्रता के साथ यह व्यापक-आधारित गिरावट उन उद्योगों और व्यवसायों के अनुरूप है जिनमें यह हुआ है। 2004-05 और 2011-12 के बीच महिलाओं की डब्ल्यूपीआर में 24.8 प्रतिशत अंक की गिरावट, अपनी जमीन पर खेती और संबद्ध गतिविधियों पर काम में गिरावट ने सबसे ज्यादा योगदान(14.8

प्रतिशत अंक) दिया। ये नियमित वेतनभोगी कार्यों में 0.7 प्रतिशत की वृद्धि और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधि नियम (MGNREGA) जैसे सार्वजनिक कार्यों के कार्यक्रमों में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि से संतुलित थे। अधिकांश गिरावट - 24.8 में से 23.1 प्रतिशत अंक कृषि और संबद्ध गतिविधियों में कम भागीदारी से आई है।

कृषि में पुरुषों की भागीदारी में भी गिरावट आई है। 15 और उससे अधिक आयु वर्ग के पुरुषों में, 56.1% ने 2004-05 में कृषि में भाग लिया, जबकि 2017-18 में केवल 39.6% ने ऐसा किया। हालांकि, पुरुष अन्य उद्योगों में काम करने में सक्षम थे, जबकि महिलाओं ने कृषि के साथ-साथ अन्य उद्योगों में भी अपनी भागीदारी कम की, जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूपीआर कम हुआ। मशीनीकरण और भूमि विखंडन ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कृषि कार्य के अवसरों को कम कर दिया है।

सार्वजनिक कार्यों के कार्यक्रमों में काम के अलावा अन्य काम के अवसर, आसानी से महिलाओं के लिए नहीं खुले हैं। यह चुनौती खासतौर पर शिक्षा के मध्यम स्तर वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए गंभीर है। कक्षा 10 तक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति डाक वाहक, ट्रक चालक या मैकेनिक हो सकता है। लेकिन यही अवसर महिलाओं के लिए नहीं खुले हैं। इसलिए, यह आश्चर्यजनक नहीं है कि शिक्षा महिलाओं के लिए कम डब्ल्यूपीआर से जुड़ी है। 2016-17 में, कम से कम माध्यमिक शिक्षा के साथ केवल 16% महिलाओं की तुलना में 29.1% निरक्षर महिलाएँ कार्यरत थीं।

महिलाओं की काम करने की इच्छा के बजाय महिलाओं के काम के अवसरों में गिरावट का एक अन्य तथ्य इस तथ्य से परिलक्षित होता है कि जिन महिलाओं को श्रम बल से बाहर गिना जाता है वे केवल गृहिणी बन कर रहने से संतुष्ट नहीं होती हैं, लेकिन अक्सर वे जो भी आर्थिक गतिविधियों को ढूंढती हैं, उसमें संलग्न होती हैं। कई ग्रामीण महिलाएँ बच्चों के साथ-साथ मुर्गियाँ भी पालती हैं तथा धान की भूसी को बेचती और बच्चों की देखभाल करते हुए बाजार में सब्जियाँ भी बेचती हैं।

एनएसएसओ और पीएलएफएस सर्वेक्षण डिजाइन दो प्रश्नों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, साक्षात्कारकर्ता प्राथमिक गतिविधि का आकलन करते हैं जिसमें उत्तरदाताओं ने अपने पूर्व वर्ष अधिकांश हिस्सा बिताया हो। फिर वे सहायक गतिविधि को नोट करते हैं जिसमें व्यक्तियों ने कम से कम 30 दिन बिताए हो। यदि व्यक्तियों को प्राथमिक या सहायक मानदंड द्वारा काम करने के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उन्हें श्रमिकों में गिना जाता है।

यह एक वर्गीकरण है, जो उन मामलों में अच्छा कार्य करता है। जहाँ कृषि प्राथमिक गतिविधि है और 30 दिन की दहलीज को समाहित करने के लिए कृषि से संबंधित विभिन्न कार्यों को एक साथ रखा जा सकता है। लेकिन, जैसे-जैसे कृषि कार्य की माँग घटती जाती है और महिलाएँ विविध गतिविधियों में संलग्न होती जाती हैं, उनका काम विभाजित हो जाता है।

एक महिला जो बुवाई की अवधि के दौरान अपने स्वयं के क्षेत्र में 15 दिन खर्च करती है, एक निर्माण मजदूर के रूप में 10 दिन और मनरेगा के काम में 15 दिन सहायक स्थिति मानदंडों का उपयोग करते हुए एक कार्यकर्ता के रूप में गिना जाना चाहिए। लेकिन कोई भी गतिविधि 30 दिनों से अधिक नहीं होती है। यह काफी संभव है कि साक्षात्कारकर्ता उसे नियोजित होने के रूप में चिह्नित नहीं करते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नेशनल डेटा इनोवेशन सेंटर (एनसीएईआर-एनडीआईसी) में चल रहे प्रायोगिक अनुसंधान यह बताते है कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मानक श्रम शक्ति प्रश्नों का उपयोग करके महिलाओं के काम का बहुत कम गणना हो पाता हैं।यह ये नहीं बताता है कि सर्वेक्षण में कम गणना की समस्या का समाधान डब्ल्यूपीआर में गिरावट का समाधान है।

संभव समाधान

रोजगार और कौशल विकास पर कैबिनेट समिति की स्थापना नई सरकार द्वारा स्वागत योग्य कदम है। यह आशा की जानी चाहिए कि यह समिति महिला रोजगार में गिरावट के मुद्दे को गंभीरता से लेगी क्योंकि यह युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को उठाती है। सभी नीतियाँ लिंग आधारित हो, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। यदि कैबिनेट समिति बहु-क्षेत्रीय सुधारों पर ध्यान केंद्रित करती है, जो महिलाओं के काम के अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, तो संभावित लैंगिक लाभांश बहुत अधिक जनसांख्यिकीय लाभांश से अधिक हो सकता है।

GS World
Committed to Excellence

एनएनएनओ एवं सीएसओ के विलय हेतु मंजूरी

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्री य प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) में विलय करने का फैसला किया है।
- मंत्रालय द्वारा यह कदम भारतीय आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली के संबंध में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कामकाज को सुव्यवस्थित और मजबूत करने तथा मंत्रालय के भीतर प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करके अधिक तालमेल बैठाने के लिए उठाया गया है।

मुख्य बिंदु

- इस नई व्यवस्था के तहत सांख्यिकी शाखा, मुख्य मंत्रालय का एक अभिन्न हिस्सा होगा।
- एनएसओ के साथ घटक के रूप में सीएसओ और एनएसएसओ शामिल होंगे।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव एनएसएसओ की अध्यक्षता करेंगे। इसके विभिन्न विभाग महानिदेशक (डीजी) के जरिये सचिव को रिपोर्ट करेंगे।
- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) वृहद आर्थिक आंकड़े जैसे जीडीपी वृद्धि, औद्योगिक उत्पादन और मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करता है। इसका प्रमुख महानिदेशक होता है।

नये विभाग और उनके कार्य

- अब एनएसएसओ के डेटा प्रसंस्करण विभाग (डीपीडी) का नाम डेटा क्वालिटी एश्योरेंस विभाग (डीक्यूएडी) होगा।
- इस पर सर्वेक्षण के आंकड़ों और गैर - सर्वेक्षण आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने की जिम्मेदारी होगी। गैर - सर्वेक्षण डेटा में आर्थिक गणना और प्रशासनिक आंकड़ों जैसी चीजें शामिल हैं।
- इसी प्रकार, एनएसएसओ का फील्ड ऑपरेशन विभाग (एफओडी) मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय होगा।
- सीएसओ, एनएसएसओ के अन्य सभी विभाग और प्रशासनिक शाखा मंत्रालय के अन्य विभागों के रूप में मौजूद रहेंगे।
- आदेश में राष्ट्रीय संख्यिकी आयोग (एनएससी) को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया। यह देश में सांख्यिकी कार्यों की निगरानी करता है। सरकार ने एक जून 2005 का एनएससी की स्थापना की थी।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ)

- यह भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संगठन है।यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत्त कार्य करता है।
- इसके कार्यकलापों में राष्ट्रीय लेखा के संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन भी शामिल है।
- केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का प्रमुख महानिदेशक होता है जिसकी सहायतार्थ पांच अपर महानिदेशक होते हैं, जो राष्ट्रीय लेखा प्रभाग, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, अर्थ-सांख्यिकी प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग और समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग का कार्य देखते हैं।

Commit

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **'केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-**

1. यह भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास हेतु उत्तरदायी संगठन है।
2. यह संगठन भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, के अंतर्गत कार्य करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

Q. In the context of 'Central Statistical Organization', consider the following statements:

1. It is a organization responsible for coordinating statistical activities and developing statistical standards in India.
2. This organization works under the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न:- हाल ही में श्रम शक्ति सर्वेक्षण द्वारा जारी एक रिपोर्ट में ग्रामीण महिलाओं के रोजगार में गिरावट देखी गयी है। इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार में सुधार करने हेतु उपाय बताइए। (250 शब्द)

Q. Recently, a report released by the Survey of Labor Force has shown a decline in the employment of rural women. Explain the reasons for this, and explain ways to improve the employment of rural areas.

(250Words)

नोट : 11 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b), 2(d) होगा।

Comm.